

लोकसभा अध्यक्ष अपने “डिस्केशनरी फण्ड” का बहुत “सही” उपयोग कर रहे हैं!

अविश्वास प्रस्ताव को बेअसर करने के लिए, 60 देशों में सांसदों के प्रतिनिधिमंडल भेजे जाएंगे लोकसभा सचिवालय की ओर से, भारत की संसदीय व्यवस्था की सुंदर कहानी पेश करने के लिए

-रेणु मि्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 फरवरी। क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला अपने व्यक्तिगत पीआर के लिए राष्ट्रीय खजाने का दुरुपयोग कर रहे हैं? लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 9 मार्च को सदन में चर्चा के लिए लाया जाएगा। जब सदन एक ब्रेक के बाद फिर से चलेगा, उसी दिन प्रस्ताव लाया जाएगा। सांसदों और अधिकारियों के बीच गुप्तचुप चर्चा हो रही है कि स्पीकर ने भारतीय संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बड़ी तादाद में नेताओं व सांसदों को 60 देशों में भेजने का कार्यक्रम बनाया है।

विभिन्न समूह बनाए गए हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के ऑपरेशन सिंदूर के बाद के दौर में किए गए प्रयासों की तरह ही विभिन्न देशों के साथ संपर्क बनाने का

- इस मकसद से 60 से अधिक देशों के साथ संसदीय मित्रता ग्रुप बनाए गए हैं।
- विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं, जैसे पी. चिदम्बरम, शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, टी.आर. बालू, के.सी. वेणुगोपाल, अखिलेश, ओवैसी, अभिषेक बनर्जी, सुप्रिया सूले, अनुराग ठाकुर आदि को संसदीय मित्रता ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया है।
- श्री लंका, जर्मनी, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इजरायल, अमेरिका, रूस, यूरोपीयन यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ईरान व यू.ए.ई., को भेजे जाने वाले ग्रुप्स गठित हो चुके हैं तथा साथ ही इस सूची में सम्मिलित नाम साठ की संख्या पार कर जाएंगे।
- ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्र.मंत्री ने भी कई ग्रुप्स बनाये थे, जिन्हें विदेश भेजा गया था तथा इन ग्रुप्स की यात्रा का काफी व्यापक व सकारात्मक असर हुआ था। ओम बिड़ला चाह रहे हैं कि संसदीय ग्रुप की वर्तमान विदेश यात्राओं से भी ऐसा ही नतीजा निकलेगा।
- यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लोकसभाध्यक्ष के “डिस्केशनरी फण्ड” का कोई ऑडिट नहीं होता, राष्ट्रपति के “डिस्केशनरी फण्ड” की भांति। अतः संसदीय मंत्री ग्रुप्स की विदेश यात्राएं निर्विज्ज रूप से पूर्ण होगी शीघ्र ही।

कार्य करेंगे, ताकि भारत के दृष्टिकोण को सामने लाया जा सके।

कहा जा रहा है कि स्पीकर के खिलाफ चल रही आलोचनाओं को

दबाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जल्दी ही अलवर तक भी आएगी रैपिड रेल

दिल्ली से मेरठ तक का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 फरवरी। भारत का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस), जो दिल्ली से 82 किमी की दूर स्थित मेरठ को जोड़ेगा, अब पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को इस लाइन के अग्रे 26 किमी खंड का उद्घाटन किया। ट्रेनों का परिचालन 10 मिनट के अंतराल पर होगा, जो दिल्ली के समय काले खान से लेकर मेरठ के मोदीपुरम तक की यात्रा 55 मिनट में पूरी करेगी।

साथ ही, मेरठ मेट्रो का 23 किमी का खंड भी लॉन्च किया गया है- जो आरआरटीएस ट्रेकों और सिग्नलिंग सिस्टम का उपयोग करेगा। अधिकारियों ने कहा, इसे भारत की सबसे तेज मेट्रो रेल प्रणाली के रूप में पेश किया गया है, जिसकी अधिकतम संचालन गति 120 किमी/घंटा होगी,

- प्रधानमंत्री ने रविवार को पहले रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विधिवत् उद्घाटन किया।
- इसी बीच केन्द्रीय शहरी मामलात मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली-अलवर और दिल्ली-करनाल रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की बात कही।
- पहले रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के शुभारंभ के साथ ही मेरठ मेट्रो का 23 किलोमीटर लंबा रेल खंड भी शुरू किया गया। अब देश का मेट्रो रेल नेटवर्क 1100 किलोमीटर तक बढ़ चुका है।

और पूरी यात्रा 30 मिनट में पूरी होगी। यात्री चार स्टेशनों पर आरआरटीएस और मेट्रो इंटरचेंज कर सकते हैं: मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगम पुल और मोदीपुरम।

अधिकारियों ने कहा, अब मेरठ के जुड़ने से, देश का मेट्रो नेटवर्क 24 शहरों में 1,100 किमी तक बढ़ चुका

है।

180 किमी/घंटा की डिजाइन स्पीड और 160 किमी/घंटा की संचालन स्पीड के साथ, दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस भारत का पहला परिवहन प्रोजेक्ट है, जो क्लस्टर-आधारित शहरी विकास की अवधारणा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन पुनः बिखराव की ओर

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 फरवरी। आगामी राज्य सभा और महाराष्ट्र विधान परिषद

- इस बार मसला है, राज्यसभा की रिक्त हुई सीटों का। महाराष्ट्र से राज्यसभा की सात सीटें खाली होंगी, इनमें से सिर्फ एक विपक्ष को मिलेगी और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के तीनों घटक, शिव सेना, कांग्रेस व एनसीपी की इस एक सीट पर नजर है।

चुनावों ने विपक्षी खेमें में हलचल मचा दी है और महा विकास अघाड़ी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रांची से दिल्ली जा रही एयर एंबुलेंस क्रैश

रांची, 23 फरवरी। रांची से एक मरीज को इलाज के लिए दिल्ली लेकर जा रही एक एयर एंबुलेंस सोमवार रात चतरा में क्रैश हो गई। इस विमान पर मरीज समेत कुल सात लोग सवार थे, जिनमें सभी की मौत हो गई।

बताया जाता है कि आग से गंभीर रूप से झुलसे, लातेहार के चंदवा निवासी मरीज संजय कुमार को शाम 7:11 बजे रांची के देवकमल अस्पताल से दिल्ली ले जाया जा रहा था। रेड बर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड के, बीच क्राफ्ट सी 90 एयर एंबुलेंस में

- चतरा जिले के पास सिमरिया में हुए हादसे में विमान में सवार मरीज सहित सभी सात लोगों की मौत हो गई।

मरीज संजय कुमार, उनकी पत्नी अर्चना देवी व एक अन्य स्वजन ध्रुव कुमार के अलावा एंबुलेंस टीम के कैप्टन विवेक विकास भगत, कैप्टन स्वराज दीप सिंह, डॉ. विकास कुमार गुप्ता और पैरा मेडिकल स्टाफ सचिन कुमार गुप्ता सवार थे।

रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि शाम 7.34 बजे एयर टैफिक कंट्रोल (एटीसी) से विमान का संपर्क अचानक टूट गया। संपर्क टूटते ही तत्काल हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हरदीप पुरी के बारे में नया विवाद खड़ा हुआ, एफ्टीन से संबंधों के बारे में

सोशल एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला ने पुरी का एफ्टीन को लिखा एक पत्र ट्विटर पर डाला

- इस पत्र के अनुसार, पुरी ने एफ्टीन के एक नजदीकी मित्र को 2013 में पत्र लिखकर धन्यवाद दिया, पुरी की पुत्री हिमानी पुरी की व्यवसायिक कंपनी में 2,400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए। यह उस समय की बात है जब 2013 में, हरदीप पुरी भारत की “फॉरेन सर्विस” की पोस्ट, यू.एन. में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के पद से रिटायर हुए ही थे तथा उन पर आरोप था कि वे कंपनी से सम्बद्ध बिज़नेस के लिए “लॉबिंग” कर रहे थे।
- इस प्रसंग का एक रोचक पहलू यह भी है कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा की बड़ी सुस्त सी प्रतिक्रिया आई। खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस इस प्रकरण से जुड़े कागज़ातों की सच्चाई व विश्वसनीयता का गहराई से अध्ययन कर रही है तथा निष्कर्ष पर पहुँचकर ही अपनी प्रतिक्रिया देगी।

कुछ वर्ग इस मामले में स्पष्टता की मांग कर रहे हैं।

विवाद ने तब जोर पकड़ा जब सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए इसे पुरी का निजी पत्र बताया। अपनी पोस्ट में शुक्ला ने आरोप लगाया कि राजनयिक सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद

पुरी न्यूयॉर्क में अपनी बेटी के कारोबारी हितों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे।

हालांकि, इस दस्तावेज की प्रामाणिकता और पत्राचार के संदर्भ की अब तक आधिकारिक खोजों से स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

असम में कांग्रेस से पलायन रोकना बड़ी चुनौती है प्रियंका के लिए

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भूपेन बोरा ने भाजपा में शामिल होकर प्रियंका के लिए चुनौती बढ़ा दी है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 फरवरी। असम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष के रूप में जिम्मेमदारी संभालते हुए, कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने राज्य का दो दिवसीय दौरा पूरा किया। यह दौरा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा के पार्टी से इस्तीफा देने के कुछ ही दिन बाद हुआ। करीब 30 वर्षों तक कांग्रेस में रहे बोरा, जो जुलाई 2021 से मई 2025 तक असम इकाई के अध्यक्ष रहे, ने शुक्रवार को पार्टी छोड़ दी। सूत्रों के अनुसार, जब से गौरव गोगोई उनकी जगह राज्य पार्टी अध्यक्ष बने हैं, तब से वे असहज महसूस कर रहे थे। उन्हें लगता था कि नए प्रदेश अध्यक्ष धुबरी के सांसद रकीबुल हुसैन को अधिक महत्व दे रहे हैं।

- प्रियंका गांधी स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष हैं और उन पर सही प्रत्याशियों के चयन की भी जिम्मेवारी है, साथ ही गठबंधन के लिए सही सहयोगियों की तलाश भी उन्हें करनी है। इसके लिए वे फूक-फूक कर कदम उठा रही हैं।

- अपने हालिया असम दौरे में उन्होंने राज्य के सभी कांग्रेसी विधायकों, सांसदों व जिला तथा ब्लॉक अध्यक्षों से भी मुलाकात की।

- सूत्रों का कहना है कि राज्य में भाजपा का संगठन काफी मजबूत है, कांग्रेस भले ही बड़ी जीत प्राप्त न कर पाए, पर, अगर उसने स्थिति पहले से बेहतर कर ली तो भी इससे प्रियंका की सफलता माना जाएगा।

शुक्रवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद,

एनडीटीवी से बातचीत में बोरा ने कहा कि वे रविवार को भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 8 मार्च

तक कांग्रेस के कई अन्य नेता भी भाजपा में जा सकते हैं।

प्रियंका गांधी के लिए अब सबसे बड़ी प्राथमिकता इस संभावित पलायन को रोकना और चुनाव से पहले पार्टी को

एकजुट रखना होगा।

स्क्रीनिंग कमेटी के अन्य सदस्यों में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री, डी के शिवकुमार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद इमरान मसूदर शामिल हैं। अपने दौरे के दौरान, गांधी ने असम के 21 विधायकों, तीन सांसदों, जिला अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों से मुलाकात की।

उम्मीदवारों के चयन के अलावा, गांधी और कांग्रेस के सामने एक और बड़ी चुनौती भाजपा का सामना करने के लिए सही सहयोगियों का चयन करना होगा। ज्ञातव्य है कि भाजपा लगातार दो कार्यकाल से सत्ता में है और चुनाव से पहले उसे बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। 2021 में, भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने राज्य की 126 में से 75 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाजोड़ को केवल 50 सीटें मिली थीं। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अनिल अंबानी पर बैंक की कार्यवाही से रोक हटी

मुंबई, 23 फरवरी। उद्योगपति अनिल अंबानी को बॉम्बे हाई कोर्ट से सोमवार झटका लगा। अदालत ने वह स्टे आदेश हटा दिया, जिसने बैंकों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोक रखा था। कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज की उस अंतरिम राहत को

- बॉम्बे हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच का स्टे हटाया।

रद्द कर दिया, जिसमें तीन बैंकों, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और आईडीबीआई बैंक तथा ऑडिटर बीडीओ इंडिया एलएलपी को कार्रवाई से रोका गया था।

यह पूरा मामला आरबीआई की 2024 मास्टर डायरेक्शंस ऑन फ्रॉड क्लासिफिकेशन से जुड़ा है। सिंगल जज ने दिसंबर 2025 में अनिल अंबानी को राहत देते हुए कहा था कि फॉरेसिक ऑडिट रिपोर्ट को तैयार करने वाले (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

मेरे दोस्त किसी चीज़ को कुरूप ना कहो, सिवाय उस भय के जिसकी मारी कोई आत्मा स्वयं अपनी स्मृतियों से डरने लगे। –खलील जिब्रान

AI (Artificial Intelligence), AI (Aam Insaan) के लिये काम आए तो कितना अच्छा हो

17 से 20 फरवरी 2026 के दौरान भारत द्वारा पूरे विश्व की सबसे बड़ी AI summit आयोजित की गई। इसमें कई राष्ट्र अध्यक्षों के साथ ही लगभग 100 देशों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विशेषज्ञों ने भाग लिया और इसके विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की। इस सफल आयोजन के लिए भारत सरकार बधाई की पात्र है, इसके बावजूद कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन द्वारा विकसित रोबोट कुत्ते, ओरियन को अपना बताते हुए प्रस्तुत किया, जिससे काफी शर्मिंदा होना पड़ा।

इसके अतिरिक्त, युवा कांग्रेस के सदस्यों द्वारा किया गया बिना शर्ट के बेहूदा प्रदर्शन भी कोई अच्छा निर्णय नहीं था। इससे विश्व में भारत की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ा। यह बात भी सही है कि अब भारत द्वारा एआइ पर अधिक बल दिया जा रहा है, जबकि इस क्षेत्र में चीन हमसे बहुत-बहुत आगे निकल चुका है। फिर भी यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि इस क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने इस पर इसे उच्च प्राथमिकता तो दी है।

अब प्रश्न यह उठता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ देश के किस वर्ग को मिलता है? क्या इसका लाभ वही ले पाएंगे जो पहले ही विकास की दौड़ में आगे हैं, सक्षम हैं और समर्थ हैं? यदि ऐसा हुआ तो देश में असमानता, जो पहले ही बहुत अधिक है, और अधिक बढ जाएगी। इससे देश में असंतोष बढ़ने की संभावना रहेगी। सरकार को यह समझना होगा कि एआइ तो एक हथियार मात्र है। इसके माध्यम से हम क्या हासिल करना चाहते हैं, यह सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

देश में वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि इन्हें हमारे देश के वंचित वर्ग की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए एआइ का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाए। पाठकों के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में शोध एवं विकास पर बहुत ही काम धनराशि खर्च की जाती है, जब कि विकसित देश इस पर हमसे कई गुना अधिक खर्च करते हैं। चीन भी इस क्षेत्र में भारत से बहुत अधिक व्यय कर रहा है और यही इस क्षेत्र में उसकी अप्रतिम सफलता का आधार भी है। सातवें दशक के अंत में चीन ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और उसका उसे भरपूर मिल रहा है। पूरे विश्व में उसके वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ छाप हुए हैं। एक सर्वे में यह बताया गया कि कुछ वर्षों पूर्व जहां 64 महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में से 57 में अमेरिका प्रथम स्थान पर था वहीं यह केवल 6 में प्रथम स्थान पर रहा है और 54 में चीन ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। एक प्रकार से तकनीकी विशेषज्ञता के महत्वपूर्ण क्षेत्र में चीन ने सभी को पीछे छोड़ दिया है, यहाँ तक कि अमेरिका भी उससे बहुत पीछे हो गया है।

अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हमें इसका उपयोग अब आम ईसान (एआइ) के लिए करने की जरूरत है। इनमें अधिकतर वे लोग हैं जो हार्शिए पर हैं। इनकी वास्तविक स्थिति का अंदाज़ा किसी भी गांव में जाने पर अथवा किसी भी शहर की कच्ची बस्ती में कुछ दर रकने से ही लग जाता है। ये वे लोग हैं जिनके बच्चों को या तो शिक्षा नहीं मिलती है या मिलती भी है तो कुछ इस प्रकार की, कि उसका जीवन में कोई उपयोग नहीं है। उन्हें जिस सरकारी भवन में बैठकर पढ़ाई करनी होती है, वह कब ध्वस्त हो जाएगा और उनकी जान ले लेगा, इसकी आशंका सदैव बनी रहती है। इन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा का अर्थ ही नहीं है क्योंकि उनके गांव में बिजली कभी कभार ही आती है। इन्हें दूषित पानी पीकर अस्वस्थता की ओर धकेल दिया जाता है। इन्हें अपने गांव में पानी शुद्ध नहीं मिलने के कारण और स्वास्थ्य सुविधा न होने के कारण अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय इन्हीं के जुगाड़ में बिता देना पड़ता है। यदि एआइ उनके लिए कुछ समस्याओं का हल खोज सके और उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर सके तो भारत के संदर्भ में यह कहीं अधिक उपयुक्त होगा। अब तक केवल प्रशासनिक आधार पर उनकी समस्याओं का

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सरकारी धन के दुरुपयोग पर एआइ के प्रभावी उपयोग से कड़ा अंकुश लगाया जा सकता है। इससे वास्तविक पात्र शत प्रतिशत लोगों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ मिल सकेगा। सरकार में पैसे की कमी नहीं, अपितु उसके उपयोग पर कड़ी और सही मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। यही काम एआइ की सहायता से बखूबी किया जा सकता है। आवश्यकता केवल इच्छा शक्ति की है। इसको कार्यान्वित करने के तो एआइ ने असीमित द्वार खोल दिए हैं।

यदि जवाब देही का काम एआइ के माध्यम से बेहतर तरीके से हो जाए तो न केवल इससे प्रशासनिक व्ययस्था सुदृढ़ होगी अपितु इससे भ्रष्टाचार पर चोट करने में भी सहायता मिलेगी। एआइ के उपयोग के बाद भ्रष्ट नेता और अफसर की मनमानी पर अंकुश लगने की संभावना बनेगी। बिना किसी विलंब के एआइ के उपयोग से कई समस्याओं का हल निकालना संभव हो जाएगा।

अपराध नियंत्रण में एआइ का बहुत बड़ा उपयोग होने की संभावना है। ऐसा करने पर गरीब लोगों को शोषण से बचाए जा सकेगा और यदि किसी ने ऐसा किया भी तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना अवश्य ही संभव हो जाएगा।

मैं यह सोचता हूँ कि यदि हम एआइ का उपयोग निम्न समस्याओं का हल निकालने में कर सकें तो यह आम ईसानों की प्राप्ति अर्थात देश की सर्वांगीण प्रगति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा:— एआइ से यह पता लगाना चाहिए कि जो लोग आयुष्मान योजना के अंतर्गत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के हकदार हैं, उनमें से कितनों को इसका लाभ मिला और जिन्हें नहीं मिला उसकी जानकारी तत्काल सबको उपलब्ध हो जाए। जिनके कारण लाभ नहीं मिला उनका विवरण भी तत्काल सार्वजनिक हो जाय तो भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं होगी।

जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उनकी सही जानकारी मोहल्लावार, बटन दबाते ही मिल जाए तो संसाधनों का दुरुपयोग रोका जा सकेगा और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस क्षेत्र में काम करने में सुविधा होगी। जो विद्यार्थी सरकारी योजना के अंतर्गत लैपटॉप, स्कूटी, साइकिल आदि प्राप्त करने के अधिकारी हैं, उन सबको यह सुविधा मिल जाए, इसे सुनिश्चित किया जा सकता है। एआइ की सहायता से सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों के शैक्षिक स्तर का आंकलन करना संभव है और इसके आधार पर शिक्षकों को जवाबदेह बनाया जा सकेगा। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदोन्नति में भी इसके आधार पर एआइ को काम में लिया जा सकता है।

हाल ही में साइबर फ्रॉड के अनेक मामले सामने आ रहे हैं। क्या इन्हें रोकने में एआइ की मदद नहीं ली जा सकती?

बैकों से लिए गये ऋण का सदुपयोग हुआ या नहीं यह पता करना सरल है, एआइ और अन्य तकनीकों का उपयोग करके।

श्रमिकों, विद्यार्थियों, कृषकों, महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं किंतु यों भ्रष्टाचार के कारण वास्तविक पात्र तो वंचित रह जाते हैं और तिकड़मबाज लोग, भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों से मिलकर सरकारी पैसे को चूना लगाने में सफल हो जाते हैं। इनकी पहचान एआइ के माध्यम से करना न केवल संभव, अपितु आवश्यक भी है।

अनेक प्रभावशाली संप्रदाय, गरीब बनकर, गरीबों के लिए बनी योजनाओं का पैसा हड़प लेते हैं। इस पर अंकुश लगाया जा सकता है, ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए खर्चों की एआइ की सहायता से निगरानी करके। इससे इनकी संपन्नता सामने आ जाएगी।

कई लोग औद्योगिक क्षेत्रों में सस्ती ज़मीनें खरीद कर बिना उद्योग लगाए कुछ समय बाद इन्हें ऊंचे दामों में बेचकर गलत रूप से पैसा बना लेते हैं। इसे एआइ की सहायता से रोका जा सकता है, क्योंकि जिओ टैगिंग करके आर्वाइट भूखंड की मौके की वास्तविक स्थिति ज्ञात की जा सकती है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सरकारी धन के दुरुपयोग पर एआइ के प्रभावी उपयोग से कड़ा अंकुश लगाया जा सकता है। इससे वास्तविक पात्र शत प्रतिशत लोगों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ मिल सकेगा। सरकार में पैसे की कमी नहीं, अपितु उसके उपयोग पर कड़ी और सही मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। यही काम एआइ की सहायता से बखूबी किया जा सकता है।

आवश्यकता केवल इच्छा शक्ति की है। इसको कार्यान्वित करने के तो एआइ ने असीमित द्वार खोल दिए हैं।

आशा है, सरकार एआइ समिट की सफलता को “Aam Insaan” (AI) की बेहतरी में काम लेगी। संक्षेप में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) का उपयोग AI यानि “(Aam Insaan)” के लिए करने का समय आ गया है। यदि हम ऐसा करने में सफल हो पाए तो इस समिट की सार्थकता कई गुणा बढ जाएगी।

–अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

मरुस्थल की धड़कन : पोकरण शौर्य, राजनीति और परमाणु शक्ति की ऐतिहासिक नगरी



जुगल किशोर बिस्सा

पश्चिमी राजस्थान की तपती रेत के बीच बसा पोकरण केवल एक कस्बा नहीं, बल्कि इतिहास, कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का जीवंत प्रतीक है। राजपूत शौर्य की गाथाओं से लेकर आधुनिक भारत की परमाणु शक्ति तक, इस मरुस्थलीय नगरी ने हर युग में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

रियासतकाल की गौरवगाथा: लालकिला और चम्पावत ठिकाना

पोकरण की स्थापना लगभग 14वीं शताब्दी (1356 ई.) में मानी जाती है। यहाँ स्थित भव्य पोकरण लालकिला (बालागढ़) आज भी राठौड़ वीरता और स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। राजपूत समाज के पोकरणा जाती, मारवाड़ के संस्थापक राव जोधा के वंश से जुड़े चम्पावत राठौड़ यहाँ के ठिकानेदार रहे। पोकरण ठिकाने को मारवाड़ दरबार (जोधपुर) में विशेष सम्मान प्राप्त था और स्थानीय प्रशासन में इसकी निर्णायक भूमिका मानी जाती थी। लाल पत्थर से निर्मित यह किला मरुस्थलीय स्थापत्य की श्रेष्ठ धरोहर है।

व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र – करियासत काल में पोकरण पश्चिमी व्यापारिक मार्गों का महत्वपूर्ण पड़ाव

था। ऊँटों के कारवां यहाँ से सिंध, कंधार, काबुल और मध्य एशिया तक व्यापार करते थे। नमक, ऊन, मसाले और सूखे मेवों व सोना का व्यापार इस क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ था। मरुस्थल में स्थित होने के बावजूद पोकरण व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा।

ब्रिटिश काल में राजनीतिक संपर्क – 19वीं शताब्दी में जब राजपूत रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियाँ कीं, तब मारवाड़ राज्य भी ब्रिटिश संरक्षण में आया। पोकरण, मारवाड़ रियासत का



गुलाब सिंह रावलोट

प्रमुख ठिकाना होने के कारण अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे से जुड़ा रहा। ठिकानेदारों और अंग्रेज अधिकारियों के बीच कूटनीतिक संपर्क होते रहे।

रियासतकालीन राजनीति में पोकरण की भूमिका रणनीतिक मानी जाती थी। हिंदुस्तान के पहले लोकतंत्र में इतिहास रचते हुए मेजर रिटायर्ड हड़वत सिंह रावलोट लोहारकी निवासी ने जैसलमेर के पहले 1952 में विधायक बनने का गौरव प्राप्त किया, वहीं उसी परिवार के गुलाब सिंह

रावलोट ने 1993 में जैसलमेर जिले के विधानसभा में अपना दबदबा बनाए रखते हुए ऐतिहासिक मतों से भाजपा से निर्वाचित हुए। परमाणु स्थल के परमाणु नगरी के रूप में विश्व पहचान पोकरण को अंतरराष्ट्रीय पहचान तब मिली जब भारत ने यहाँ परमाणु परीक्षण किए। 18 मई 1974 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण लोहारकी गांव में किया गया। 11 और 13 मई 1998 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व खेतोलाई गांव में पाँच सफल परीक्षण



हड़वत सिंह रावलोट

किए गए। इन ऐतिहासिक घटनाओं के बाद पोकरण परमाणु नगरी के रूप में विश्व मानचित्र पर स्थापित हो गया और भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक बन गया।

लोकतंत्र की राह: राजनीति का केंद्र – स्वतंत्रता के बाद मारवाड़ रियासत भारतीय संघ में विलय हुई और राजस्थान राज्य के गठन के साथ पोकरण विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। जैसलमेर जिले के गठन के बाद पोकरण क्षेत्र ने लोकतांत्रिक राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना की उपस्थिति और विकास कार्य यहाँ प्रमुख चुनावी मुद्दे रहे हैं। जातीय और सामाजिक समीकरण- राजपूत, ब्राह्मण, महाजन, मुस्लिम, ओबीसी और अनुसूचित जाति वर्ग- चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान सीमा के निकट होने से रक्षा और विकास दोनों मुद्दे स्थानीय राजनीति का आधार बनते हैं। सेना, बीएसएफ और रक्षा परियोजनाओं की उपस्थिति स्थानीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करती है।

आस्था और संस्कृति का संगम – पोकरण क्षेत्र धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। निकट स्थित तीर्थ नगरी रामदेवरा धाम देशभर के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। स्थानीय परंपराओं में इसे भगवान परशुराम, चिड़िया नाथ जी महाराज, साघोजी

महाराज, डूंगरपुरी जी महाराज की तपोभूमि भी माना जाता है। धर्म, शौर्य और राष्ट्रभक्ति की त्रिवेणी ने पोकरण की पहचान को विशिष्ट बनाया है।

पोकरण का इतिहास तीन प्रमुख आयामों में स्पष्ट होता है- राजपूत ठिकाना और किला संस्कृति

मरुस्थलीय व्यापार और रियासती राजनीति

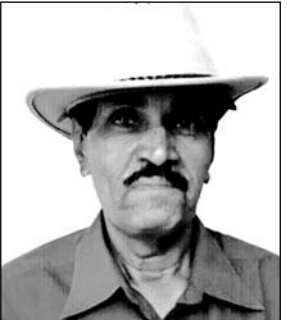
भारत की परमाणु शक्ति और आधुनिक सामरिक पहचान

आज पोकरण केवल जैसलमेर जिले का प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि राजनीतिक चाणक्य नगरी, शौर्य भूमि और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। मरुस्थल की यह धड़कन आज भी इतिहास और आधुनिक युग के बीच सेतु बनकर खड़ी है।

–जुगल किशोर बिस्सा, वरिष्ठ पत्रकार

‘आवारा कुत्तों’ पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जनमानस में उबाल

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में बंद करने का आदेश दिया था, आदेश के बाद देशभर में डॉग लवर्स का आक्रोश फूट पड़ा



मिश्रीलाल पंवार

इन दिनों आवारा कुत्तों को लेकर देश में एक जंग छिड़ी हुई है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट को दर्जनों की बेंच ने दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच बैठी और दो जजों की बेंच के आदेश में संशोधन किया। यह फैसला 11 अगस्त 2025 के उस आदेश को कम नहीं आया, जिसमें सभी कुत्तों को शेल्टर में रखने की बात कही गई थी, जिसे 22 अगस्त 2025 को संशोधित कर दिया गया। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजोरिया की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर शैक्षिक संस्थान, अस्पताल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड, डिपो, रेलवे स्टेशनों इत्यादि की अच्छी तरह से बाड़बंदी जरूरी है, ताकि आवारा कुत्तों को घुसने से रोका जा सके। तीन न्यायाधीशों के इस जजमेंट के बाद डॉग लवर्स और पशु प्रेमी कार्यकर्ताओं को काफी राहत मिली।

जोधपुर निवासी मंजू दहिया ने कहा कि मनुष्य सैकड़ों हजारों वर्षों से अन्य जीवों के साथ प्रेम पूर्वक रहता आया है। प्रकृति ने सबको जीने का समान अधिकार दिया है। अगर मनुष्य खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने तथा अन्य जीवों को धरती का बोझ समझने की भूल करेगा तो ईश्वर कोरोगा जैसी आपदा से मनुष्य को सजा देने में भी

विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए सोशल मीडिया पर जीव हितेषियों ने हाहाकार मचा दिया। परिणाम यह हुआ कि दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच बैठी और दो जजों की बेंच के आदेश में संशोधन किया। यह फैसला 11 अगस्त 2025 के उस आदेश को कम नहीं आया, जिसमें सभी कुत्तों को शेल्टर में रखने की बात कही गई थी, जिसे 22 अगस्त 2025 को संशोधित कर दिया गया। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजोरिया की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर शैक्षिक संस्थान, अस्पताल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड, डिपो, रेलवे स्टेशनों इत्यादि की अच्छी तरह से बाड़बंदी जरूरी है, ताकि आवारा कुत्तों को घुसने से रोका जा सके। तीन न्यायाधीशों के इस जजमेंट के बाद डॉग लवर्स और पशु प्रेमी कार्यकर्ताओं को काफी राहत मिली।

जोधपुर निवासी मंजू दहिया ने कहा कि मनुष्य सैकड़ों हजारों वर्षों से अन्य जीवों के साथ प्रेम पूर्वक रहता आया है। प्रकृति ने सबको जीने का समान अधिकार दिया है। अगर मनुष्य खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने तथा अन्य जीवों को धरती का बोझ समझने की भूल करेगा तो ईश्वर कोरोगा जैसी आपदा से मनुष्य को सजा देने में भी

देरी नहीं करेगा। मनुष्य को ऊपर वाले के जजमेंट से थोड़ा डरना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भी सनातनी परंपरा में घर की माताएं पहली रोटी गाय के लिए तथा दूसरी रोटी कुत्ते के लिए निकालती है। दुनिया की किसी कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि गाय कुत्तों के लिए प्रथम रोटी देने वाली मां को जेल भेजने की बात करें। उन्होंने कहा कि मूक पशु बोल नहीं सकते, इसका मतलब यह तो नहीं कि उन्हें ईसाफ नहीं चाहिए।

इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि भारतीय संस्कृति में सब जीवों को बराबर का दर्जा दिया गया है। संत नामदेव और कुत्ते का प्रसंग आज दुनिया में किसी से छुपा नहीं है। महान संत नामदेव एक दिन भोजन बना रहे थे। उन्होंने रोटी बनाई और सोचा कि संस्कृति के इस जजमेंट के बाद भोग लगा लूं। उन्होंने रोटी बनाकर रखी ही थी कि एक कुत्ता अचानक से उनकी कुटिया में आया और रोटी लेकर भाग गया। संत नामदेव ने देखा तो विचार किया कि मैंने रोटी पर घी तो लगाया ही नहीं।

उनकी ईश्वर के प्रति अटूट आस्था और सर्वव्यापी दृष्टि थी। कुत्ता नामदेव की रोटियां लेकर भागा, तो वे हाथ में घी का कटोरा लेकर पीछे लड़े। बोले, ‘रोटी रखी है, मख खाओ’ कहते-कहते कुत्ते के पीछे दौड़ते रहे। कुत्ता आगे-आगे और संत नामदेव पीछे-पीछे भागने लगे। हाथ में कटोरा लिए संत नामदेव से तेजी से नहीं भागा

जा रहा था। इसलिए वे जोर-जोर से आवाज भी लगाते रहे कि ‘प्रभु, रोटी पर घी तो लगाते दो।’

दरअसल संत नामदेव हर जीव में भगवान का दर्शन करते थे। उन्हें उस कुत्ते में भगवान नजर आ रहे थे। रोटी में घी लगाकर खिलाना चाहते थे, ताकि प्रभु को रूखी रोटी न खानी पड़े। यह प्रसंग इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति में अन्य जीवों में भगवान का स्वरूप देखने की परम्परा रही है।

हिंदू धर्म में कुत्ते को भगवान भैरव (शिव के उग्र रूप) का वाहन माना गया है, जो सुरक्षा, निष्ठा और सतर्कता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ कथाओं में कुत्ते को यमदूत का सहचर और मृत्यु के बाद आत्माओं का मार्गदर्शक भी माना गया है। कुछ लोकमान्यताओं में कुत्तों को सीधे भैरव बाबा का अवतार भी माना जाता है। संक्षेप में, कुत्ता हिंदू धर्म में एक पवित्र प्राणी है, जो सुरक्षा, निष्ठा और संरक्षण का प्रतीक है।

कुत्ते को लेकर एक अन्य प्रसंग भी बहुत प्रसिद्ध है। महाभारत के अंत के बाद पाण्डव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण यात्रा पर निकल पड़े थे। ब्रह्मनाथ के बाद जब पाण्डव हिमालय की पहाड़ियों में आगे बढ़ने लगे तो एक कुत्ता उनके साथ-साथ चल पड़ता है। मार्ग में द्रौपदी, सदेव, नकुल, अर्जुन और भीम की मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर पर दुखों का पहलू टूट पड़ता है। कुत्ता भी उनके दुख में

सहभागी बना रहा। कुछ विश्राम के बाद युधिष्ठिर स्वर्गारोहण यात्रा पर आगे के लिए रवाना हो गए। इस दौरान वह कुत्ता भी उनके साथ रवाना हो गया। दोनों चलते चलते सतोपंथ तीर्थ पहुंचे। वहां स्नान के बाद जब युधिष्ठिर कुत्ते के साथ यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे तो भगवान इंद्र अपने रथ के साथ उठें लेने आए। धर्मराज युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ते को देखा तो इन्द्र ने कुत्ते को स्वर्ग में ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कुत्ते के साथ स्वर्ग प्रवेश वर्जित है। उस कुत्ते को यहीं छोड़ना पड़ेगा।

इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने दृढ़ता से कहा कि जिसने अंतिम समय में मेरा साथ दिया, वफादारी निभाई, उसे अंतिम क्षण में नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा, “स्वर्ग का सुख इस वफादार साथी को छोड़ने के दुःख के आगे कुछ भी नहीं है।”

धर्मराज युधिष्ठिर की जीव के प्रति करुणा देखकर भगवान इन्द्र प्रसन्न हो उठे। इतने में कुत्ते के रूप में मौजूद धर्मदेव अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए कुत्ते का रुप धारण किया था। हिन्दू धर्म के ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं, जिसमें कुत्ते तथा गाय को ‘आवारा’ नहीं बल्कि, ‘पूज्यनीय’ बताया गया है।

–मिश्रीलाल पंवार, (लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार हैं)

 मेष आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयास सफल रहेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।	 सिंह व्यावसायिक कार्यों में आरही परेशानियां दूर होने लगेगी। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुमनता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	 धनु स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।
 वृष मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। आज व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	 कन्या परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।	 मकर व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नौकरियां व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।
 मिथुन आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। शुभ कार्यों में भय है। अनावश्यक धन खर्च होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में संयम रखना ठीक रहेगा।	 तुला चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज व्यावसायिक कार्यों के कारण मानसिक तनाव बना रहेगा।	 कुंभ घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
 कर्क आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संपातित स्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।	 वृश्चिक परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में आज धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।	 मीन परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कांग्रेस विधायक दल की बैठक में धारीवाल और डोटासरा के बीच हुई तीखी बहस

डोटासरा द्वारा बैठक में बोलने का अवसर न दिए जाने से नाराज होकर शांति धारीवाल बैठक छोड़कर चले गए और बाद में सदन में भी उपस्थित नहीं रहे

-विधानसभा संवाददाता-
जयपुर। राजस्थान विधानसभा की “ना पक्ष” लॉबी में सोमवार सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कांग्रेस के अधिकांश विधायक शामिल हुए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे और चर्चा में भाग लिया। बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के बीच बहस भी हुई। डोटासरा द्वारा बोलने का अवसर न दिए जाने से नाराज धारीवाल बैठक छोड़कर चले गए

■ बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई थी

और बाद में सदन में भी उपस्थित नहीं रहे।

बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य विधानसभा के शेष सत्र में सरकार को प्रभावी ढंग से घेरने की रणनीति तैयार करना था। हाल के दिनों में सदन में 2 साल बनाम 5 साल के

मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बहस और हंगामा हुआ था। शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार के 2 वर्षीय कार्यकाल की उपलब्धियों का प्रतिवेदन पेश किया और कांग्रेस के 5 साल के शासन की तुलना में बेहतर प्रदर्शन का दावा किया, जिसके विरोध में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया था। इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने बैठक

में तय किया कि वह सदन में आक्रामक रुख अपनाएगी और सरकार की कमियों को उजागर करेगी। रणनीति के तहत कांग्रेस ने कई प्रमुख मुद्दों पर फोकस करने का फैसला किया। इनमें बंदरों के आतंक से किसानों-नागरिकों की परेशानी, पेंशन संबंधी शिकायतें, महंगाई, बेरोजगारी, किसान कर्जमाफी की प्रगति, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की खामियां शामिल हैं। कांग्रेस विधायक दल ने तीन विभागों की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान सरकार से सवालों की बाँछार करने की योजना बनाई। साथ ही,

प्रश्नकाल में विभागीय जवाबदेही सुनिश्चित करने और याचिकाओं के माध्यम से जनहित के मुद्दे उठाने पर जोर दिया गया। जूली ने बैठक के बाद संकेत दिए कि कांग्रेस अब सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि ठोस विकल्प पेश करेगी। मुख्य सचेतक रफीक खान ने बताया कि विधायकों में एकजुटता दिखी और सभी ने सरकार की घोषणाओं पर आधारित राजनीति की आलोचना की। बैठक में यह भी तय हुआ कि सत्र के दौरान हंगामे से बचते हुए जनता से जुड़े मुद्दों पर लगातार दबाव बनाया जाएगा।

पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करें : भजनलाल शर्मा

8 गीगावाट बिजली उत्पादन के लिए चिन्हित 6 पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ली।

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को पर्याप्त और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि बिजली बचाना भी विद्युत उत्पादन के समान है।

■ किसानों को पर्याप्त और निर्बाध बिजली आपूर्ति राज्य सरकार की प्राथमिकता : सीएम

इसी क्रम में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जमीनी स्तर पर सघन दौर कर बिजली चोरी के मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाए। शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट्स सस्ते होने के साथ ही लम्बी

अवधि के लिए कारगर हैं, जिससे आने वाले समय में पर्याप्त बिजली मिलना संभव हो सकेगा। इससे किसानों के साथ-साथ घरेलू उपभोक्ता को भी गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जाए, ताकि इनका लाभ उपभोक्ताओं को शीघ्र मिल सके।

उन्होंने प्रोजेक्ट्स की क्लियरेंस के लिए विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय स्थापित करने एवं कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने सभी राजकीय कार्यालयों पर जल्द से जल्द सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन कार्यालयों में अब तक सोलर पैनल नहीं लगे हैं, उन्हें सूचीबद्ध कर शीघ्र कार्य शुरू किया जाए। बैठक में 8 गीगावाट बिजली उत्पादन के लिए चिन्हित 6 प्रोजेक्ट्स पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी. श्रीनिवास सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

बीकानेर में नाबालिग से दुष्कर्म-हत्या को लेकर सदन में हंगामा, कांग्रेस ने किया वॉकआउट

गृह राज्यमंत्री ने सदन में कहा “पुलिस जांच जारी है, जल्द ही आरोपी पकड़ लिए जाएंगे”

-विधानसभा संवाददाता-
जयपुर। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को शून्यकाल के दौरान बीकानेर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर तीखी नोकझोंक और हंगामा हुआ। आरोप-प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया।

शून्यकाल में कांग्रेस विधायक हंगाराम गेदर ने बीकानेर की घटना को उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। इस पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने कहा कि मामले में पुलिस जांच जारी है। नाबालिग का शव मोचरी में रखा गया है और बीकानेर के पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।

■ परंतु नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि “प्रदेश में लगातार दुष्कर्म की घटनाएं सामने आने के बावजूद सरकार अपराध नियंत्रण पर गंभीरता से काम नहीं कर रही।”

उन्होंने आश्वासन दिया कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी कब होगी, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि

यदि सरकार अपराध नियंत्रण पर गंभीरता से काम करती तो ऐसी घटनाएं नहीं होतीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस पर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने नेता प्रतिपक्ष पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। जवाब में बेदम ने कहा कि एक गंभीर अपराध के मामले में भी राजनीति करना उचित नहीं है और इसे ओछी राजनीति बताया। इस पर टीकाराम जूली ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बारे में पूछना राजनीति नहीं है। इससे पहले, विधानसभा में इस प्रकरण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई।

44 ग्राम गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार

जयपुर। अवैध मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत मानसरोवर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी महिला तस्कर के कब्जे से 44 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ की जा रही है।

बालिका से दुष्कर्म-हत्या के दोषियों की जल्द होगी गिरफ्तारी : भाटी

जयपुर (विसं)। कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने विधानसभा परिसर में सोमवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के बच्चे, तहसील अंतर्गत सीमावर्ती उप-तहसील रंजीतपुरा गाँव में एक अत्यंत दुःखद एवं संवेदनशील घटना सामने आई है।

यहां 21 फरवरी को एक 12 वर्षीय बालिका अपने घर से परीक्षा देने

के लिए निकली थी, जिसे दोपहर 1 बजे परीक्षा केंद्र पहुंचना था, परंतु वह नहीं पहुंची।

उन्होंने बताया कि विद्यालय प्रशासन द्वारा परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद परिजन एवं ग्रामीणों ने खोजबीन प्रारंभ की। खोज के दौरान बालिका का शव रंजीतपुरा गाँव के समीप स्थित एक पोखर में मिला। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक एवं आक्रोश

का माहौल है। भाटी ने कहा सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। शाम तक उच्च अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक भी घटनास्थल पर पहुंच गए।

मामले को गंभीरता को देखते हुए विभिन्न जांच कमेटियों का गठन किया गया है तथा एफएसएल टीम द्वारा साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। प्रशासन द्वारा शीघ्र ही दोषियों को गिरफ्तार करने का

आश्वासन दिया गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि दोषियों को गिरफ्तारी से पूर्व पोस्टमॉर्टम नहीं कराया जाएगा। इसी मांग को लेकर 22 फरवरी से धरना जारी है। प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर समाधान का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन से मांग है कि दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

धौलपुर में सैचुरी से रास्तें बंद

जयपुर (विसं)। कांग्रेस विधायक संजय जाटव ने धौलपुर जिले में सैचुरी क्षेत्रों के कारण ग्रामीणों को हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि चिन विभाग ने गांवों के रास्ते बंद कर दिए हैं और फोर्स तैनात कर दी गई है। जाटव ने कहा कि जिन गांवों को उनके पूर्वजों ने सदियों पहले बसाया, आज वहां के लोगों को घुट-घुटकर जीना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम सभाओं के फैसलों को नहीं माना जा रहा और परंपरागत नैन भूमि से लोगों को बेदखल किया जा रहा है।

‘विपक्ष के पास ना खुद की उपलब्धियां और ना ही कोई मुद्दा, इसलिए कर रहे है हंगामा’

जयपुर (विसं)। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने विधानसभा में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सरकार के सवा दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सदन में दिए गए वक्तव्य ने राज्य की राजनीति में व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि जो कार्य पूर्ववर्ती सरकार अपने पाँच वर्ष के कार्यकाल में नहीं कर पाई, वे कार्य वर्तमान सरकार ने अल्प

समय में पूर्ण कर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस दल में हलचल तेज हो गई है।

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेतृत्व में आंतरिक असंतोष भी देखा गया है। यह भी सामने आया है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी सदन में भूमिका को लेकर सवाल किए गए हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व ने यह भी पूछा कि यदि पूर्व

सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए थे, तो उन्हें सदन में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया। इसी संदर्भ में हाल के दिनों में पार्टी के भीतर चल रही आंतरिक मतभेदों की चर्चाएं भी तेज हुई हैं, बताया जा रहा है कि हाल ही में दिल्ली में हुई बैठकों के दौरान प्रदेश नेतृत्व को विधानसभा में अपेक्षित प्रदर्शन न करने को लेकर भी फटकार मिली। विशेष रूप से यह मुद्दा उठाया गया कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर

प्रभावी ढंग से पक्ष नहीं रखा गया। इस दौरान हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि हमारी सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए व ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उपचुनावों में विकास के दम पर हमें विजय प्राप्त हुई। कांग्रेस सिर्फ घोषणाएं करती है काम नहीं करती। कांग्रेस सदन में चर्चा में भाग नहीं ले रही है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस दलित विरोधी है तथा दलित नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है।

जयपुर को मिली ब्रिक्स बैठक की मेजबानी

मुख्य सचिव ने की ब्रिक्स वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक की तैयारियों पर चर्चा

जयपुर (कासं)। जयपुर में आयोजित होने वाली ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की प्रथम बैठक की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव बी. श्रीनिवास ने सचिवालय में सोमवार को समीक्षा बैठक ली। बैठक में आर्थिक मामलों विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने कहा कि जयपुर में इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन राज्य के लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। यह अवसर राज्य की संस्कृति, पर्यटन, विकास और प्रशासनिक क्षमता को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए समग्रबद्ध रूप से तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने 4 से 7 मार्च के प्रस्तावित कार्यक्रमों में मंत्रिस्तरीय बैठक, प्रतिनिधियों के आगमन, आवास, परिवहन, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण तथा अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि



मुख्य सचिव बी. श्रीनिवास ने जयपुर में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियों को लेकर सोमवार को उच्चाधिकारियों की बैठक ली।

प्रतिनिधिमंडलों की आवाजाही के लिए सुचारु परिचालन व्यवस्था, पायलट वाहन तथा आवश्यकतानुसार रूट क्लियरेंस सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आयोजन स्थल, होटलों, भ्रमण स्थलों के निर्देश दिए। उन्होंने शहर के प्रमुख मार्गों, आयोजन स्थलों एवं भ्रमण मार्गों की साफ-सफाई, सौंदर्यीकरण और

खरखाब सुनिश्चित करने को कहा। स्वास्थ्य विधायकों के तहत 24 घंटे चिकित्सा दल, एम्बुलेंस, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता तथा नजदीकी अस्पतालों से समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने आमेर किले में प्रस्तावित भ्रमण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा

करते हुए कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, लोकनृत्य, संगीत और आतिथ्य की परंपरा को झलक विश्व समुदाय को दिखनी चाहिए। प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षित गाइड, पार्किंग व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रतिनिधियों के लिए राज्य की कला

एवं हस्तशिल्प से जुड़े स्मृति-चिह्न तैयार करने तथा पर्यटन पुस्तिका की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडलों के साथ समन्वय के लिए लयोजन अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में आर्थिक मामलों विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव अनु पी. मथई, संयुक्त सचिव अमित सिंगला और निदेशक प्रकाश राजपुरोहित सहित जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन एवं सांस्कृतिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग भास्कर आत्माराम सावंत, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग गायत्री ए. राठौड़, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग वैभव गालरिया, प्रमुख शासन सचिव गरीय विकास विभाग डॉ. देबाशीष पट्टी, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग नवीन जैन, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (इंटरलिजेंस), पुलिस आयुक्त जयपुर, विभिन्न विभागों के शासन सचिव तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

“ 2 साल बनाम 5 साल ’’ पर सियासी बयानबाजी तेज

राजेन्द्र राठौड़ ने गहलोत को दी खुली बहस की चुनौती

जयपुर (कासं)। राजस्थान में दो साल बनाम पांच साल को लेकर सियासी घमासान और तेज हो गया है। पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “एक्स” पर ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री के हालिया बयान पर तीखा पलटवार किया है। राठौड़ ने गहलोत के बयान को “उल्टा बांस बेली” वाली कहावत बताया।

राठौड़ ने कहा कि 21 फरवरी को विधानसभा में वर्तमान और पूर्ववर्ती सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा निर्धारित थी। यह बहस प्रदेश की जनता के सामने दोनों कार्यकालों की उपलब्धियों और नीतियों के तुलनात्मक विश्लेषण रखने का अवसर था, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने सुनियोजित तरीके से हंगामा कर चर्चा से किनारा कर लिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास अपने 5 साल के कार्यकाल का

ठोस रीपोर्ट कार्ड नहीं था, इसलिए बहस से बचने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री स्वयं सदन में उपस्थित थे और विपक्ष के हर प्रश्न का तथ्यात्मक उत्तर देने के लिए तैयार थे।

इसके बावजूद कांग्रेस ने सदन में अपनी बात रखने के बजाय बाहर बयानबाजी का रास्ता चुना।

कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर राठौड़ ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रदेश में अपराध और महिला अत्याचार के मामलों को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार के दो वर्षों में कुल अपराधों में लगभग 14 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

उनके अनुसार, हत्याओं में 25 प्रतिशत, हत्या के प्रयास में 19 प्रतिशत, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 10 प्रतिशत, अनुसूचित जाति-जनजाति के विरुद्ध अत्याचारों में 28 प्रतिशत,

डकैती में 47 प्रतिशत और लुटपाट में 51 प्रतिशत की कमी आई है। राठौड़ ने विकास कार्यों को लेकर भी गहलोत सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं और योजनाओं का श्रेय गहलोत ले रहे हैं, वे धरातल पर मौजूदा सरकार के कार्यक्रमों में साकार हुई हैं।

उन्होंने गहलोत को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि कानून-व्यवस्था, विकास या शासन के किसी भी पहलू को लेकर कोई शंका है तो सदन में खुली और तथ्याधारित बहस की जाए।

जनता सब देख रही है और तथ्यों के आधार पर निर्णय करना जानती है। राठौड़ के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने नजर आ रहे हैं। दो साल बनाम पांच साल का मुद्दा आने वाले दिनों में और ज्यादा राजनीतिक गर्मी पैदा कर सकता है।

भट्टा बस्ती में चाकू मारकर किशोर की हत्या, दो आरोपी हिरासत में

जयपुर। भट्टा बस्ती इलाके में मामूली कहासुनी के बाद युवक (किशोर) की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

पुलिस के अनुसार घटना भोमियाजी की बस्ती की है। यहां रहने वाले आदिल का आसपास के कुछ युवकों से विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी झगड़े में बदल गई और आरोपियों ने आदिल पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल आदिल को अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (उत्तर) बजरंग सिंह

शेखावत ने बताया कि मृतक के परिजनों की शिकायत पर समीर,अरबाज सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस से त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार कहासुनी और विवाद हो चुका था। रविवार रात मामूली बात को लेकर विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया और कुछ लोग भट्टा बस्ती थाने के बाहर आरोपियों की गिरफ्तारी का मांग को लेकर थाने का बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। तब पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और पूरे मामले को गहन जांच जारी है।

अधिवक्ता मौलिक अधिकारों के रक्षक की भूमिका निभाते हैं- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने द बार एसोसिएशन जयपुर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ दिलाई

जयपुर, 23 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता कानून की कठिन भाषा को सरल बनाकर समाज को न्याय दिलाने वाले सेतु हैं।

सोमवार को बनीपार्क स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में दी बार एसोसिएशन जयपुर के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अधिवक्ता संविधान एवं मौलिक अधिकारों के रक्षक तथा लोकतंत्र के प्रहरी की भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं को न केवल पेशेवर मंच प्रदान करता है, बल्कि बौद्धिक विमर्श, नैतिक अनुशासन और सामूहिक शक्ति का भी केंद्र है।

उन्होंने कहा कि यह संस्था विधिक सुधारों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। 42 नए न्यायालय स्थापित किए गए हैं। फ़ौजदारी, खैरथल-तिजारा सहित कुल 8 जिला एवं सेशन न्यायालयों का सुजन किया गया है। लॉबत प्रकरणों के शीघ्र निस्तारा हेतु विशेष अदालतों एवं फास्ट ट्रैक तंत्र को अधिक सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को बनीपार्क स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में दी बार एसोसिएशन जयपुर के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित किया।

महाराष्ट्र में विपक्षी ...

(**प्रथम पृष्ठ का शेष**)
(एमवीए) के पार्टनर्स शिवसेना (उद्धव ठाकरे), कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार) के बीच टकराव की अटकलों को जन्म दे दिया है।

महाराष्ट्र से सात राज्य सभा सीटें रिक्त होने जा रही हैं। इन सीटों में से दो कांग्रेस के पास हैं, एक शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के पास और एक एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के पास है। राज्य सभा के चुनाव में मतदान विधायक करते हैं और 2024 महाराष्ट्र चुनावों में एनडीए की शानदार जीत के कारण इन सात सीटों में से छह सीटें एनडीए की झोली में जा सकती हैं। इसका मतलब है कि विपक्ष के पास केवल एक सीट बचती है। शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के

नेता उद्धव ठाकरे कथित तौर पर दिल्ली यात्रा की योजना बना रहे हैं, ताकि कांग्रेस के उच्च नेतृत्व से बातचीत की जा सके। इस बीच, सूत्रों ने बताया कि एनसीपी (शरद पवार) प्रारंभिक बातचीत का हिस्सा नहीं रही है, जिससे विपक्षी खेमे के भीतर समीकरणों को

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 2 6 फरवरी को

नई दिल्ली, 23 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 26 फरवरी तक टाल दी है।

जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज की सुनवाई सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता के उपलब्ध नहीं होने की वजह से टाली।

गीतांजलि ने 19 फरवरी को उच्चतम न्यायालय से कहा था कि जिन चार वीडियो के आधार पर गिरफ्तार किया गया वो वीडियो सोनम वांगचुक को दिखाया ही नहीं गया। केवल पेन ड्राइंग में

लोकसभा अध्यक्ष अपने ...

(**प्रथम पृष्ठ का शेष**)
है, स्पीकर की गलतियों व कृत्यों के कारण उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया गया है।

लोकसभा स्पीकर ने वैश्विक लोकतांत्रिक संबंधों को मजबूत करने के नाम पर 60 से अधिक देशों के साथ संसदीय मित्रता समूहों का गठन किया है और इसके लिए बड़ी रकम खर्च की जा रही है। लोकसभा स्पीकर के पास एक विवेकाधीन कोष होता है, लेकिन इसका ऑडिट नहीं होता, क्योंकि वह एक संप्रभु अधिकारी है, और इस कोष के खर्च पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता और न ही इस पर चर्चा हो सकती है। यही स्थिति भारत के राष्ट्रपति के कोष के साथ भी है।

विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता इन समूहों का नेतृत्व करेंगे, जो भारत की लोकतांत्रिक विविधता और शक्ति को 60 से अधिक देशों के सामने उजागर करेंगे।

जो नेता इन प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करेंगे, उनमें पी. चिदंबरम, शशि थरूर, रवि शंकर प्रसाद, टी.आर. बालू, के. एस. गेणगोपाल, अखिलेश यादव, ओबेसैी, अणुपम कर्नाठी, सुप्रिया सुले और अनुराग ठाकुर शामिल हैं।

ट्रंप कहा ...

(**प्रथम पृष्ठ का शेष**)
लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी इस तथाकथित सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति को और घेरने की रणनीति बना रही है। वे लोगों को टैरिफ पेमेंट तुरंत आगे बढ़ाने के लिए कानून बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने डॉनल्ड ट्रंप को एक चिड़चिड़े, आवेगी, बिना सोचे-समझे काम करने वाले और प्लानिंग के रूप में उजागर किया है।

उनके कदमों का जो भी परिणाम हो, वे अपनी प्रतिशोध की योजनाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस फैसले के बाद, शी जिनपिंग के साथ डॉनल्ड ट्रंप की आगामी बैठक साफ तौर पर एकतरफा होगी।

अधिवक्ताओं की न्यायसंगत मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। कार्यक्रम में हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल उपमन ने कहा कि राज्य के बजट से विधि क्षेत्र को थोड़ी निराशा हुई है। उन्होंने अदालत परिसर और संसाधनों की जरूरत बताते हुए कहा कि सरकार को विधि क्षेत्र के लिए भी ध्यान देने की जरूरत है। यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रां ने कहा कि अधिवक्ता वर्ग की समस्याएं हैं, उनका निराकरण किया जाएगा।

कार्यक्रम में सीएम ने एसोसिएशन के निर्वाचित अध्यक्ष सोमश चन्द शर्मा व महासचिव उमेश चौधरी एवं जिला बार एसोसिएशन के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल उपमन ने कहा कि राज्य के बजट से विधि क्षेत्र को थोड़ी निराशा हुई है। उन्होंने अदालत परिसर और संसाधनों की जरूरत बताते हुए कहा कि सरकार को विधि क्षेत्र के लिए भी ध्यान देने की जरूरत है। यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रां ने कहा कि अधिवक्ता वर्ग की समस्याएं हैं, उनका निराकरण किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम ने एसोसिएशन के निर्वाचित अध्यक्ष सोमश चन्द शर्मा व महासचिव उमेश चौधरी एवं जिला बार एसोसिएशन के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई।

‘ भारत टैक्सी दुनिया की सबसे पारदर्शी कैब सर्विस बनेगी ’

केन्द्रीय गृहमंत्री अमितशाह ने भारत टैक्सी के सारथियों (चालक) के साथ संवाद में कहा

नई दिल्ली, 23 फरवरी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि हाल ही में शुरू की गई सहकारी टैक्सी सेवा “भारत टैक्सी” अपने मंच से जुड़े सभी ‘सारथियों’ (चालकों) के लिए प्रति किलोमीटर न्यूनतम आधार किराया सुनिश्चित करेगी और इस दर से नीचे सेवा संचालित नहीं की जाएगी।

शाह ने कहा, भारत टैक्सी में ऑटो की लागत, पेट्रोल की खपत और न्यूनतम लाभ को जोड़कर बेस रेट निर्धारित किया जाएगा। यह सेवा पारदर्शिता के सिद्धांत पर काम करेगी और किसी भी बदलाव की सूचना एक सप्ताह पहले सारथियों

■ **शाह ने कहा, यह सहकारी टैक्सी सेवा सभी सारथियों के लिए प्रति किलोमीटर न्यूनतम किराया तय करेगी।**

को मोबाइल पर दी जाएगी। अमित शाह ने कहा, भारत टैक्सी में कुछ भी छिपा नहीं होगा। सारथियों को नोटिफिकेशन के जरिए हर जानकारी देने से ‘भारत टैक्सी’ दुनिया की सबसे पारदर्शी कैब सर्विस बनेगी। भारत टैक्सी सारथियों की मिनिमम वार्यबिलिटी के आधार पर एक

ट्रंप कहा ...

(**प्रथम पृष्ठ का शेष**)
लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी इस तथाकथित सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति को और घेरने की रणनीति बना रही है। वे लोगों को टैरिफ पेमेंट तुरंत आगे बढ़ाने के लिए कानून बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने डॉनल्ड ट्रंप को एक चिड़चिड़े, आवेगी, बिना सोचे-समझे काम करने वाले और प्लानिंग के रूप में उजागर किया है।

उनके कदमों का जो भी परिणाम हो, वे अपनी प्रतिशोध की योजनाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस फैसले के बाद, शी जिनपिंग के साथ डॉनल्ड ट्रंप की आगामी बैठक साफ तौर पर एकतरफा होगी।

अधिवक्ताओं की न्यायसंगत मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। कार्यक्रम में हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल उपमन ने कहा कि राज्य के बजट से विधि क्षेत्र को थोड़ी निराशा हुई है। उन्होंने अदालत परिसर और संसाधनों की जरूरत बताते हुए कहा कि सरकार को विधि क्षेत्र के लिए भी ध्यान देने की जरूरत है। यूडीएच मंत्री झाबरसिंह खर्रां ने कहा कि अधिवक्ता वर्ग की समस्याएं हैं, उनका निराकरण किया जाएगा।

नई दिल्ली, 23 फरवरी। तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम पद की शपथ लेने के साथ ही रहमान ने देश में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। रहमान ने सेना में टॉप लेवल पर बड़ा फेरबदल किया है। तारिक रहमान ने ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हफीजुर रहमान को भारत से बांग्लादेश वापस बुला लिया है। हफीजुर रहमान भारत में बांग्लादेश हाई कमीशन में डिफेंस एडवाइजर के तौर पर काम

बारां में 4 0 करोड़ रूपए के अवैध विस्फोटक व पटाखे पकड़े गए

बारां, 23 फरवरी (निसं) ।अटरू–बारां मेन रोड स्थित मंडोला के पास फर्म आर.डी. ब्रदर्स के तीन गोदामों में अवैध विस्फोटक निर्माण सामग्री और भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण मिलने पर पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त टीम ने छापेमारी कर करीब 40 करोड़ रुपये की सामग्री जब्त कर तीनों गोदामों को सील कर दिया।

अभिषेक अंदासु, पुलिस अधीक्षक बारां ने बताया कि 20 फरवरी को सूचना मिली थी कि गोदामों में अत्यधिक मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री जमा की गई है, जिससे आसपास के रहवासियों की जान को खतरा हो सकता है।

अभिषेक अंदासु, पुलिस अधीक्षक बारां ने बताया कि 20 फरवरी को सूचना मिली थी कि गोदामों में अत्यधिक मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री जमा की गई है, जिससे आसपास के रहवासियों की जान को खतरा हो सकता है।

बांग्लादेश में भारी सैन्य फेरबदल किया नई सरकार ने

■ **रहमान ने भारत में कार्यरत बांग्लादेश हाईकमीशन के डिफेंस एडवाइज़र हफीजुर रहमान को भी वापस बुला लिया है।**

कर रहे थे। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, इन बदलावों का असर कई अहम स्ट्रेटेजिक कमांड्स के साथ–साथ बांग्लादेश की सबसे बड़ी मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी पर भी पड़ेगा। पीएम रहमान ने भारत में

किश्तवाड़ में सेना ने सात खुंखार आतंकी मारे

जम्मू, 23 फरवरी। किश्तवाड़ जिले के चतरू क्षेत्र में 326 दिनों तक चले एक संयुक्त अभियान में सात खुंखार आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सेना की वाइट नाइट कोर ने इस अभियान को वीरतापूर्ण ढ़्दृ द बताया और कहा कि किश्तवाड़ के चुनौतीपूर्ण भूभाग और खराब मौसम की स्थिति में अथक और कठिन अभियान चलाए गए।

सेना ने कहा कि वाइट नाइट कोर के जवानों ने जम्मू और कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के समन्वय से नागरिक और सैन्य खुफिया एजेंसियों के सुव्यवस्थित खुफिया नेटवर्क के आधार पर कार्रवाई की। सुरक्षा बलों ने भीषण ठंड और जमा देने वाली ठंड में दुर्गम पहाड़ी इलाकों में आतंकवादियों का पीछा किया, जिसके परिणामस्वरूप कई बार मुठभेड़ हुई और अंततः सभी सात आतंकवादियों को मार गिराया गया।

भारत की पहली आतंकरोधी नीति “प्रहार” जारी की केन्द्र सरकार ने

नई दिल्ली, 23 फरवरी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को भारत की पहली व्यापक आतंकवाद–रोधी नीति जारी की है। इसे “प्रहार” नाम दिया गया है। इस नीति में सीमा पार से होने वाले आतंकवाद, साइबर हमलों, ड्रोन और उभरती तकनीकों के गलत इस्तेमाल जैसे खतरों का प्रमुखता से जिक्र किया गया है। नीति में यह भी बताया गया है कि केवल सीमा पार से होने वाला आतंकवाद ही खतरा नहीं है, बल्कि आपराधिक हैकर और अन्य राष्ट्र भी भारत को निशाना बना रहे हैं।

मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एनपीटी दस्तावेज में कहा गया है कि भारत आतंकवाद को किसी खास नई दिल्ली, 23 फरवरी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को भारत की पहली व्यापक आतंकवाद–रोधी नीति जारी की है। इसे “प्रहार” नाम दिया गया है। इस नीति में सीमा पार से होने वाले आतंकवाद, साइबर हमलों, ड्रोन और उभरती तकनीकों के गलत इस्तेमाल जैसे खतरों का प्रमुखता से जिक्र किया गया है। नीति में यह भी बताया गया है कि केवल सीमा पार से होने वाला आतंकवाद ही खतरा नहीं है, बल्कि आपराधिक हैकर और अन्य राष्ट्र भी भारत को निशाना बना रहे हैं।

मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एनपीटी दस्तावेज में कहा गया है कि भारत आतंकवाद को किसी खास

हरदीप पुरी के बारे में नया ...

(**प्रथम पृष्ठ का शेष**)
विवाद को और बढ़ाने वाली खबरें यह भी हैं कि रॉबर्ट मिलॉर्ड नामक व्यक्ति, जिसे कुछ रिपोर्टों में एफपीटीन का कर्मी बताया गया है, ने कथित तौर पर हिमाची पुरी, जो हरदीप पुरी की बेटी हैं – से जुड़े एक कारोबारी उपक्रम में लगभग 2,400 करोड़ रुपये का निवेश किया।

मंडीया के कुछ हिस्सों और ऑनलाइन मंचों पर फैल रहे इन दावों ने इस राजनीतिक विवाद को आर्थिक पहलू की दिे दिया है। हालांकि, जांच एजेंसियों की ओर से इस कथित निवेश की प्रकृति, आकार या वैधता के संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हरदीप सिंह पुरी, जिन्होंने पहले भी सार्वजनिक मंचों पर अन्य आरोपों का जवाब दिया है, ने इन ताजा दावों पर अभी तक कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया है। पहले के मामलों में वे यह कहते रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह की गलत गतिविधि से जोड़ने की कोशिश राजनीतिक रूप से प्रेरित है और तथ्यों पर आधारित नहीं है।

इस बीच विश्वेशी कांग्रेस पार्टी ने सावधानी भरा रुख अपनाया है। पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने तुरंत कोई आरोप लगाने से परहेज

■ **पुलिस ने आर.डी. ब्रदर्स के तीन गोदाम सील किए।**

सकता है। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कोतवाली पुलिस, नगर परिषद और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। निरीक्षण के दौरान भारी मात्रा में सूतली बम, पटाखे और विस्फोटक निर्माण सामग्री पाई गई।

पुलिस और प्रशासन ने आर.डी. ब्रदर्स के तीन गोदामों से भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक निर्माण सामग्री और पटाखे जब्त किए हैं। जब्त सामग्री की

बाजार कीमत करीब 40 करोड़ रूपए आंकी गई है। अभिषेक अंदासु, पुलिस अधीक्षक बारां ने बताया कि सूचना मिलने पर संयुक्त टीम ने छापा मारकर तीनों गोदाम सील कर दिए। कार्रवाई में 1350 कट्टे सूतली बम (338 किंवंटल), 5500 कार्टन पटाखे (1918 किंवंटल), 12 किंवंटल विस्फोटक कच्चा माल, 130 बेरी जर्दा (45 किंवंटल), पैकिंग मशीन, लाल बत्ती व अन्य सामग्री जब्त की। फर्म के खिलाफ थाना कोतवाली बारां में मामला दर्ज किया गया है। गोदामों में अग्निशमन सुरक्षा उपकरण नहीं मिले।

बांग्लादेश में भारी सैन्य फेरबदल किया नई सरकार ने

बांग्लादेश हाई कमीशन में डिफेंस एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हफीजुर रहमान को मेजर जनरल के रैंक पर प्रमोट किया है और 55वीं इन्फैंट्री डिवीजन का जीओसी नियुक्त किया है। आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से जारी

नीट -पीजी कट-ऑफ कम होने का क्या असर होगा?

■ **सर्वोच्च न्यायालय चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर इसके प्रभाव की जांच करेगा।**

नई दिल्ली, 23 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह इस बात की पड़ताल करेगा कि नीट-पीजी के कट ऑफ मार्क्स को घटाने से क्या चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है या नहीं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने नीट-पीजी के कट ऑफ मार्क्स को घटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एसएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि ये फैसला खाली सीटों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। उन्होंने कहा कि नीट पीजी न्यूनतम चिकित्सकीय योग्यता प्रमाणित करने के लिए नहीं है, बल्कि सीमित सीटों के बीच उम्मीदवारों की तुलना कर सेलेक्शन के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें सभी अभ्यर्थी पहले से

एमबीबीएस डिग्रीधारी डॉक्टर हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील गोपाल शंकरनारायणन ने फीस असमानता का भी मसला उठाया। उन्होंने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फीस 9 हजार से 27 हजार रुपये तक होती थी जबकि निजी कॉलेजों में 95 लाख से 1.50 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है। उन्होंने कहा क 50वें पर्सटाइल तक लगभग 1.3 लाख छात्र सीट उपलब्ध होने के बावजूद काफी ज्यादा फीस के कारण निजी कॉलेजों में प्रवेश नहीं ले पाते। उन्होंने निजी कॉलेजों की फीस की सीमा तय करने की मांग की।

■ **गृह मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड इस नीति में कहा गया है भारत आतंकवाद को धर्म या जाति से जोड़कर नहीं देखता।**

धर्म, जाति, राष्ट्रीयता या सभ्यता से जोड़कर नहीं देखता। इसमें यह भी कहा गया है कि देश लंबे समय से सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहा है, जिसमें जिहादी आतंकवादी संगठन और उनके मुखोटा संगठन लगातार हमलों की योजना बना रहे हैं। नीति में अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठनों के नाम का भी

बाजार कीमत करीब 40 करोड़ रूपए आंकी गई है। अभिषेक अंदासु, पुलिस अधीक्षक बारां ने बताया कि सूचना मिलने पर संयुक्त टीम ने छापा मारकर तीनों गोदाम सील कर दिए। कार्रवाई में 1350 कट्टे सूतली बम (338 किंवंटल), 5500 कार्टन पटाखे (1918 किंवंटल), 12 किंवंटल विस्फोटक कच्चा माल, 130 बेरी जर्दा (45 किंवंटल), पैकिंग मशीन, लाल बत्ती व अन्य सामग्री जब्त की। फर्म के खिलाफ थाना कोतवाली बारां में मामला दर्ज किया गया है। गोदामों में अग्निशमन सुरक्षा उपकरण नहीं मिले।

किए गए ये बदलाव प्रधानमंत्री तारिक रहमान की नई सरकार के 17 फरवरी को सत्ता संभालने के कुछ दिन बाद हुये हैं। तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने 12 फरवरी को हुए चुनावों में दो-तिहाई बहुमत हासिल किया। तारिक रहमान ने 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही मुहम्मद यूनूस का 18 महीने का शासन खत्म हुआ।